www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

सत्यमेव जयते

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क : ₹ 530

रोज़गार समाचार

साप्ताहिक

खंड 44 अंक 44 पृष्ठ 24 | नई दिल्ली 1 - 7 फरवरी 2020 | ₹ 12.00

राष्ट्रीय डेटा और अनेलिटिक्स प्लेटफार्म का लक्ष्य

नीति आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और अनेलिटिक्स प्लेटफार्म (एनडीएपी) के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट अर्थात् लक्ष्य दस्तावेज जारी किया है. इस मंच का लक्ष्य प्रचार के लिए उपलब्ध सरकारी आंकड़ों तक पहुंच को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करना है. इस मंच पर विभिन्न सरकारी वेबसाइटों से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और उसे सुसंगत ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा तथा विश्लेषण और दृश्यकरण के साधन मुहैया कराए जाएंगे. एनडीएपी उपयोग-कर्ता अनुकूल दृष्टिकोण का अनुपालन करेगा और विभिन्न हितधारकों की जरूरत के अनुसार तैयार किए गए एक सरल तथा सहज पोर्टल पर आंकड़ों की पहुंच सक्षम बनाएगा.

एनडीएपी फार्मेटों के मानकीकरण की अगुवाई करेगा, जिनमें डेटा विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तुत किया जा सके और नीति निर्माताओं, अनुसंधाताओं, आविष्कारकों, डेटा वैज्ञानिकों, पत्रकारों और आम नागरिकों के रूप में व्यापक दर्शकों की जरूरत पूरी करेगा.

भारत ने नीति निर्माताओं और कार्यक्रम कार्यान्वयन करने वालों के उपयोग के लिए डेटा सृजित करने की दिशा में व्यापक प्रगति की है. डेटा पारिस्थितिकी प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है. एनडीएपी का लक्ष्य एक ही स्थान पर इस्तेमालकर्ता अनुकूल डेटा मंच कायम करना है, जिससे भारत की डेटा पारिस्थितिकी प्रणाली का कायापलट करने में मदद मिलेगी.

नीति आयोग ने शासन के सभी क्षेत्रों में आंकड़ों के इस्तेमाल में अगुवाई की है. आयोग ने राष्ट्र को एक सरल और प्रतिबद्ध मंच उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की है, जहां एक साथ विभिन्न डेटा सेट्स को एक्सेस किया जा सकता है. डेटा प्रणाली में लंबे समय से अंतराल बने हुए हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है.

सभी डेटा सेट्स इस्तेमालकर्ता केंद्रित ढंग से प्रकाशित नहीं किए जाते हैं, जिन्हें विश्लेषित किया जा सकता है और दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है. इसके अलावा अनेक ऐसे डेटा सेट्स हैं, जो आसानी से पहुंच योग्य नहीं हैं. एनएडीपी का प्रयास है एक सरल, परस्पर संवादात्मक, दृश्य और सुदृढ़ प्लेटफार्म बनाया जाए, जो विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों के डेटा सेट्स को स्थान प्रदान करे.

इस प्लेटफार्म के विकास और प्रगति पर एक अंतर-मंत्रालयी समिति निगरानी रखेगी और प्रमुख विशेषज्ञों का एक दल इसके परामर्श ग्रुप में शामिल किया गया है, जो इस प्लेटफार्म के विकास के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा. इस प्रयास की सफलता विभिन्न हितधारकों के सहयोग और सहायता पर निर्भर करेगी.

एनडीएपी का विकास एक वर्ष की अवधि में किया जाएगा. प्लेटफार्म का प्रथम संस्करण 2021 में प्रारंभ होने की संभावना है. इस प्रयास में इस्तेमालकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और इसकी समूची विकास प्रक्रिया में विभिन्न उपयोगकर्ताओं और हितधारकों से जानकारी (फीडबैक) प्राप्त की जाएगी.

एक नजर

भारत में प्रचार के लिए प्रचुर डेटा उपलब्ध है. सरकारी विभागों ने विभिन्न प्रक्रियाओं और रिपोर्टिंग जरूरतों को डिजिटीकृत किया है, जो

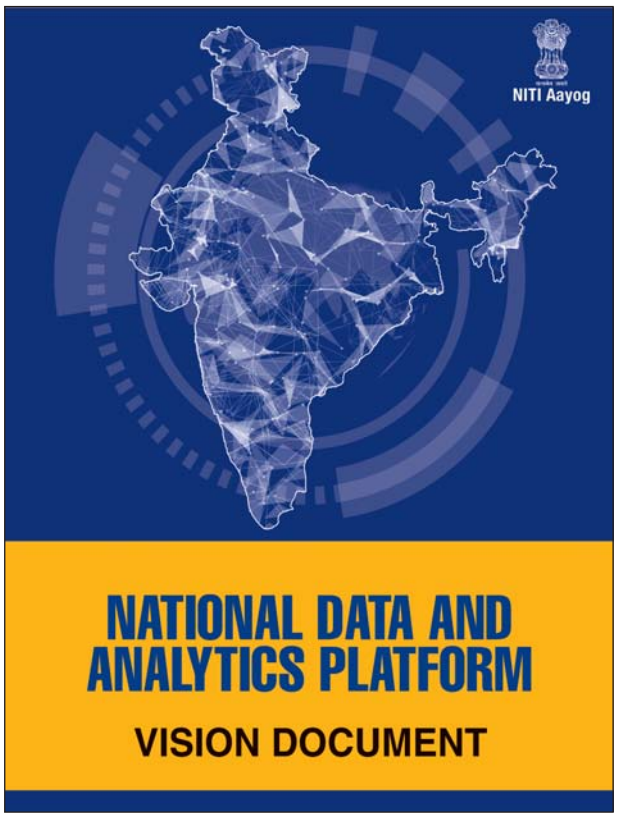

प्रबंधन सूचना प्रणालियों और परस्पर संवादात्मक डैशबोर्डों को जानकारी प्रदान करते हैं. इस जानकारी का इस्तेमाल प्रगति की दिशा तलाश करने और उसे प्रकट करने के लिए किया जाता है. साथ ही, धरातल पर सुधार परिलक्षित करने का प्रयास किया जाता है.

परंतु, आंकड़ों के इस परिदृश्य में सुधार किया जा सकता है. सभी सरकारी आंकड़ों तक सभी हितधारकों की आसान पहुंच होनी चाहिए और वह भी उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से उपलब्ध कराई जानी चाहिए. इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों से सम्बद्ध आंकड़ों को सामंजस्यपूर्ण बनाया जाना चाहिए ताकि विश्लेषण और सम्प्रेषण में मदद मिले. इतना ही नहीं, सर्वाधिक अद्यतन आंकड़ों को विश्वसनीय ढंग से प्रकाशित किया जाना चाहिए और उन तक पहुंच आसान होनी चाहिए.

लक्ष्य

इस्तेमालकर्ता केंद्रित: आंकड़ों तक पहुंच उपयोगकर्ता के अनुकूल और उसे व्यस्त रखने वाली, साथ ही नीति निर्माताओं, नौकरशाहों, अनुसंधाताओं, मौलिक चिंतकों, डेटा वैज्ञानिकों, पत्रकारों और नागरिकों की समान रूप से जरूरतें पूरी करने को ध्यान में रख कर स्थापित की जानी चाहिए.

सामंजस्यपूर्ण

बहुसंख्य डेटा सेट्स एक मानक कार्यक्रम को ध्यान में रख कर प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसके लिए साझा भू-भौतिक और सामयिक पहचानकर्ताओं का इस्तेमाल किया जाता है.

अद्यतन

जानकारी को नियमित रूप से अद्यतन करना सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की जाती हैं.

डेटा स्रोत

- केंद्र सरकार के 50 से अधिक मंत्रालयों और विभागों की वेबसाइट तथा data.gov.in पर उपलब्ध आंकड़े.
- राज्य सरकारों के सभी विभागों और मंत्रालयों की वेबसाइट, 250 से अधिक नहीं.

चुनौतियां

डेटा इस्तेमालकर्ता-केंद्रित तरीके से प्रकाशित नहीं किए जाते हैं. वर्तमान डेटा फार्मेट अक्सर अनुसंधान और नवाचार के अनुकूल नहीं हैं. अनेक विभाग दृश्यकरण के साथ सार्वजनिक डैशबोर्डों का रख-रखाव करते हैं और विश्लेषणात्मक फॉर्मेट में डेटा डाउनलोड करने का विकल्प प्रदान करते हैं. परंतु, कुछ डेटासेट्स केवल पीडीएफ, वेबपेज या इमेज के रूप में उपलब्ध हैं, जिनका आगे विश्लेषण कठिन हो जाता है. अगर इस मुद्दे का समाधान हो जाए, तो अनुसंधानकर्ताओं और डेटा वैज्ञानिकों के लिए सरकारी डेटा सेट्स को विश्लेषण के लिए मंजूरी देने और तैयार करने में समय और संसाधनों की महत्वपूर्ण बचत होगी.

विभिन्न मानकों के कारण डेटा प्रणाली सामंजस्यपूर्ण नहीं है: मंत्रालय और विभाग सामान्य संकेतकों के लिए समान मानको का इस्तेमाल नहीं करते हैं. क्षेत्र और समय अवधि संबंधी विशेषताओं को भिन्न रूप में परिभाषित किया गया है. इससे डेटा सेट्स के लिए एक दूसरे से संवाद करना और सामंजस्यपूर्ण तस्वीर पेश करना कठिन हो जाता है. यदि हम इस समस्या का समाधान कर सकें, तो बेहतर इस्तेमाल के अनेक मामले सामने आएंगे. उदाहरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट एक ही मंच पर आसानी से अपने अपने जिलों से संबंधित सभी विभागों के आंकड़ों तक आसानी से पहुंच कायम कर सकेंगे.

दृष्टिकोण

हमारा लक्ष्य विश्वभर के उत्कृष्ट प्लेटफार्मों से सीख प्राप्त करना है. लोगों द्वारा सृजित जानकारी तक पहुंच कायम करते समय इस्तेमालकर्ता अनुभव में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. इसे 'datausa.io' और 'data.gov.sg' जैसे प्लेटफार्मों पर देखा जा सकता है. ऐसे मंच की मुख्य उपयोगिता एक ही स्थान पर असंख्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के बारे में अबाधित, परस्पर संवादात्मक तरीके से जानकारी उपलब्ध कराने में निहित है. इसके अलावा ऐसे मंच मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले फार्मेट में डेटा सेट्स भी उपलब्ध कराते हैं.

हम मौजूदा भारतीय डेटा प्लेटफार्मों की सफलता से भी लाभ उठाना चाहते हैं. पिछले वर्षों में डेटा प्रकाशित करने की दिशा में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं. उदाहरण के लिए data.gov.in 165 विभागों के डेटा तक शीघ्र पहुंच उपलब्ध कराता है. इसी प्रकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिशा के जरिए 20 मंत्रालयों के 42 कार्यक्रमों के आंकड़ों तक पहुंच प्रदान की जाती है. विभिन्न राज्यों में 'चीफ मिनिस्टर डैशबोर्ड' भी कायम किए गए हैं. इस तरह के जो भी प्रयास हुए हैं, वे एनडीएपी के लिए आंकड़ों का समृद्ध स्रोत प्रदान करेंगे.

एनडीएपी डेटा तक पहुंच प्रदान करने में उपयोगकर्ता-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाएगा. इस प्लेटफार्म को इस्तेमालकर्ता अनुकूल सर्च इंजन, अबाधित नेविगेशन, विश्वस्तरीय उपयोगकर्ता इंटरफेस जैसी विशेषताओं से शक्तिशाली बनाया गया है. इसमें मशीन के लिए पठनीय रूप में आंकड़े प्रदान किए गए हैं. इस्तेमालकर्ता सर्च सुविधा पर

(शेष पृष्ठ 2 पर)

राष्ट्रीय डेटा और ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

आधारित गतिशील दृश्यीकरण किया जाएगा. प्लेटफार्म को नीति निर्माताओं, नौकरशाहों, अनुसंधानकर्ताओं, मौलिक चिंतकों, डेटा वैज्ञानिकों, पत्रकारों और नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रख कर तैयार किया जाएगा और उनके अनुकूल बनाया जाएगा.

एनडीएपी अधिसंख्य क्षेत्रों के डेटा तक एक ही स्थान से पहुंच प्रदान करेगा. केंद्र और राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे. एक साझा कार्यक्रम के जरिए इसे अंजाम दिया जाएगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता को एकसमान और अलग-अलग स्रोतों के बीच अंतरों को समझने में सहायता के लिए स्पष्ट परिभाषाएं और निर्देश दिए जाएंगे.

एनडीएपी अद्यतन आंकड़ों के लिए एक भरोसेमंद प्लेटफार्म होगा. आंकड़ों को अद्यतन करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं विकसित की जाएंगी. इन प्रक्रियाओं के अनुपालन की जांच नियमित रूप से की जाएगी. इसके अलावा डेटा को पूरी तरह अद्यतन बनाए रखने के लिए एपीआईज़ और वेब-क्रावलिंग और अन्य पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाएगा.

एनडीएपी की सफलता कारगर सहयोग पर निर्भर करेगी. एनडीएपी सिर्फ प्लेटफार्म के विकास तक सीमित नहीं रहेगा और इसके लिए व्यापक परामर्श अपेक्षित होगा. सरकार में डेटा उत्पादकों से जानकारी आवश्यक होगी ताकि डेटा स्रोतों की पहचान की जा सके और सामंजस्यपूर्ण तरीके से डेटा सेट्स के लिए डेटा प्रोसेसिंग तकनीकें

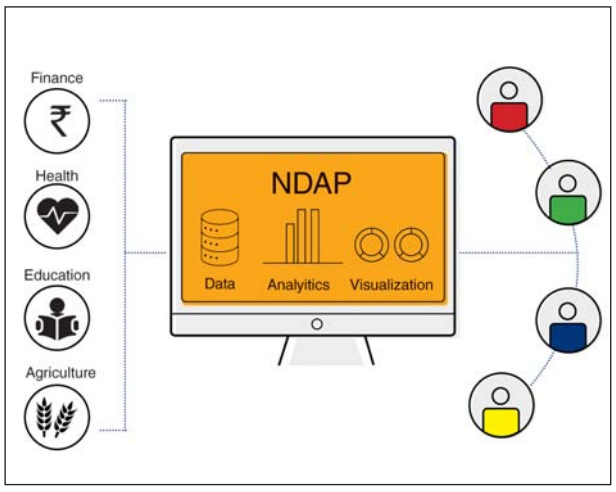

विकसित की जा सकें. इस्तेमालकर्ताओं-नीति निर्माताओं, नौकरशाहों, अनुसंधानकर्ताओं, मौलिक चिंतकों, डेटा वैज्ञानिकों, पत्रकारों और नागरिकों से नियमित फीडबैक प्राप्त किया जाएगा, जो प्लेटफार्म की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने में भी सहायता करेंगे.

एनडीएपी भारत में डेटा-संचालित संवाद, अनुसंधान, नवाचार और निर्णय करने की प्रक्रिया का रूपांतरण करने में सक्षम होगा. अद्यतन और भरोसेमंद डेटा के लिए इस प्लेटफार्म से अनेक लाभ होंगे. एनडीएपी का लक्ष्य सरकारी आंकड़ों तक जनता की लोकतांत्रिक पहुंच कायम और उसे विश्वस्तरीय इस्तेमालकर्ता अनुभव प्रदान करना है. हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि यह राष्ट्र की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध होगा.

विशेषताएं

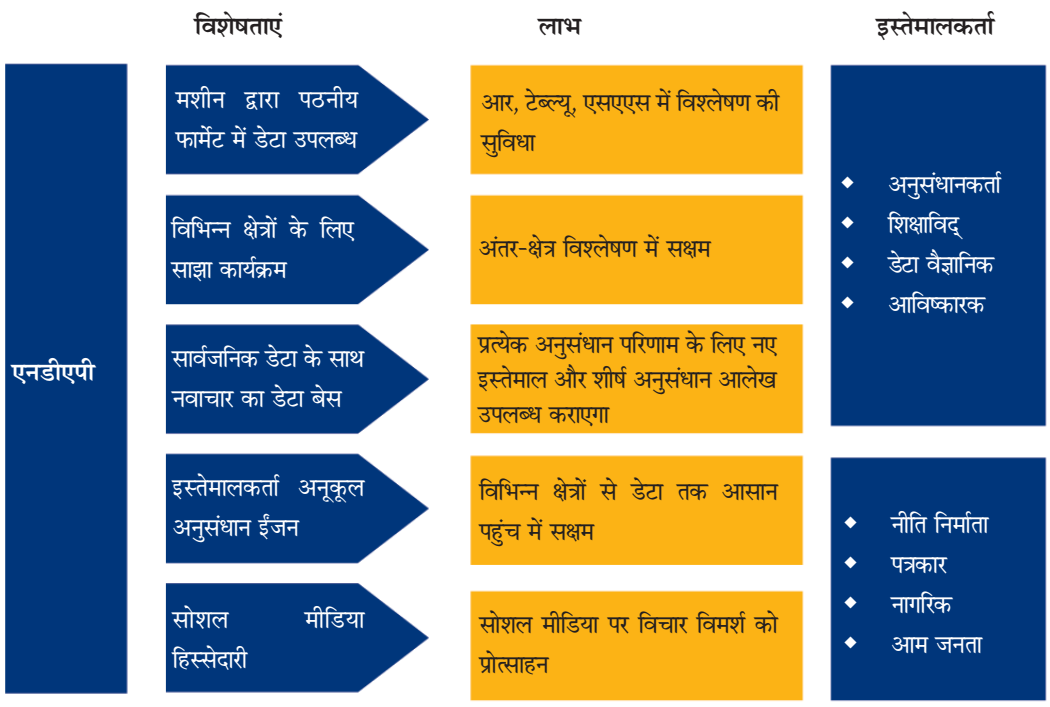

सरकारी ढांचा

उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति

नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति गठित की जाएगी, जो इस मंच को मार्गदर्शन प्रदान करेगी, इसकी प्रगति पर निगरानी रखेगी और डेटा स्रोतों के बारे में दिशा-निर्देश प्रदान करेगी तथा आंकड़ों के समन्वय के बारे में विभिन्न अंतर-मंत्रालयी मुद्दों का समाधान करेगी.

तकनीकी परामर्श समूह

एक तकनीकी सलाहकार ग्रुप का गठन किया जाएगा, जिसमें इस क्षेत्र और प्रौद्योगिकी से संबंधित विशेषज्ञ शामिल होंगे. यह ग्रुप विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करेगा. तकनीकी परामर्श ग्रुप प्लेटफार्म के विकास, आंकड़ों के प्रबंधन और प्लेटफार्म को इस्तेमालकर्ताओं की जरूरतों के अनुरूप बनाने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेगा.

परियोजना प्रबंधन यूनिट

नीति आयोग में स्थापित परियोजना प्रबंधन यूनिट एनडीएपी के विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन करेगी और विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करेगी.

प्रौद्योगिकी विक्रेता

एनडीएपी के विकास और प्रचालन के लिए एक टेक्नोलॉजी विक्रेता की सेवाएं ली जाएंगी.

तकनीकी परामर्श ग्रुप

तकनीकी सलाहकार ग्रुप के वर्तमान सदस्य इस प्रकार हैं:

- डॉ. मुदित कपूर, प्रोफेसर, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टिट्यूट
- श्री अजित पाई, ओएसडी, उपाध्यक्ष, नीति आयोग
- डॉ. आशा सुब्रमनियन, संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिमेंटिक वेब इंडिया
- डॉ. मोनोजित चौधरी, प्रधान अनुसंधानकर्ता, माइक्रोसॉफ्ट
- डॉ. ललितेश कटरागड्डा, संस्थापक, इंडिहुड
- डॉ. यामिनी अय्यर, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी, सीपीआर
- डॉ. शाम अशर, सह-संस्थापक, डिवेल्पमेंट डेटा लैब

जैसे जैसे प्लेटफार्म का विकास होगा, इस ग्रुप में अतिरिक्त सदस्य शामिल किए जाएंगे. ओमिडियार नेटवर्क इंडिया ने इस प्रयास में नीति आयोग की सहायता के लिए आईडी इन्साइट का चयन किया है.

भावी मार्ग

नेशनल डेटा और अनेलिटिक्स प्लेटफार्म का प्रथम संस्करण 2021 में जारी करने का प्रस्ताव है.

एनडीएपी नीति आयोग द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर किया गया प्रयास है. इसकी सफलता के लिए विभिन्न हितधारकों की व्यापक मदद और सहयोग अपेक्षित है. इन हितधारकों में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और विशेषज्ञ शामिल हैं, जो लक्ष्य को हासिल करने और समय सीमा का अनुपालन करने में मददगार होंगे.

(स्रोत: नीति आयोग/पीआईबी)